Value through values

SANGAM (INDIA) LIMITED

CIN : L17118 RJ 1984 PLC 003173
Regd. Office : P.B. No. 90, **ATUN**, Chittorgarh Road
Bhilwara - 311001, Rajasthan, INDIA.
Phone : + 91-1482-245400-06, Fax : + 91-1482-245450
Website: www.sangamgroup.com, E-mail : secretarial@sangamgroup.com

We run on SAP HANA

Ref: SIL/SEC/2021
Date: 29th April, 2021

The Manager Department of Corporate Services **The National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051 **Scrip Code: 5251**	The Manager, Department of Corporate Services, **Bombay Stock Exchange Ltd.** Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, MUMBAI - 400 001 **Scrip Code: 514234**

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copy of Notice published in the Newspapers.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of Notice of Board Meeting scheduled to be held on 5th May, 2021, published in Business Standard (English) and in Rajasthan Patrika (Hindi).

Hope you will find the same in order and take the same on record.

Thanking you.

For Sangam (India) Limited

(A.K. Jain)
Company Secretary
FCS – 7842

SANGAM (INDIA) LTD. Bhilwara

ब्रीफ न्यूज

एनपीसीडीसीएस बन्द होने की कगार पर

भीलवाड़ा. देशभर में डायबिटिज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कैंसर आदि की रोकथाम के लिए भारत सरकार के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय के सयुंक्त तत्वावधान में भीलवाड़ा समेत 6 राज्यों में चल रही एनपीसीडीसीएस परियोजना सेवा विस्तार नही होने के कारण 30 अप्रेल को बन्द हो रही है। इसकी जानकारी मिलने पर एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम में कार्यरत चिकित्सकों, फार्मासिस्ट, योग शिक्षको में आक्रोश और भय का माहौल है। उनका कहना है कि वे पिछले 12 महीने से कोरोना में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में चेक पोस्ट से लेकर कोविड डेडिकेटेड सेंटर पर सेवा दे रहे है। एक तरफ देश मे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार का आयुष मंत्रालय दोहरा रवैया अपनाते हुए इनको सेवा से पृथक कर रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश है।

औसत से आएंगे बिजली बिल

भीलवाड़ा. राजस्थान डिस्कॉम ने प्रदेश में कोरोना संकट काल को देखते हुए बिजली कर्मियों को घर-घर जा कर मीटर रीडिंग लेने पर रोक लगा दी है। उपभोक्ताओं को अब औसत के आधार पर आगामी बिजली बिल दिए जाएंगे। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ भीलवाड़ा वृत भामस जिलाध्यक्ष जुम्मा काठात ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में पूर्व में डिस्कॉम चेयरमैन दिनेश कुमार को ज्ञापन दे कर विद्युत कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए घर-घर जाकर रीडिंग लेने से राहत प्रदान करते हुए औसत आधार पर बिल जारी करने की मांग की थी।

तीन साध्वियों का सवाईपुर में मंगल प्रवेश

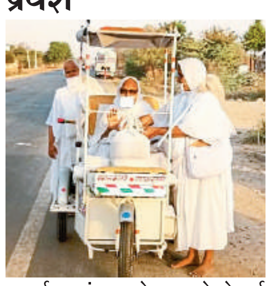

सवाईपुर मंगल प्रवेश करने से पूर्व राजमार्ग पर विहार करती हुई साध्वियां।

सवाईपुर @ पत्रिका. साध्वी मनोहर कंवर सहित तीन साध्वियों का बुधवार को कस्बे में मंगल प्रवेश किया। शांतिलाल कांकरिया ने बताया कि साध्वी मनोहर कंवर, कमल प्रभा, ऐश्वर्य प्रभा ने बन का खेड़ा से अलसुबह प्रस्थान कर सवाईपुर में मंगल प्रवेश किया।

लापरवाही बरतने पर अध्यापिका को कारण बताओ नोटिस

ऊंचा @ पत्रिका. जहाजपुर उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाली एक शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उपखंड अधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के बढते खतरे को देखते हुए कहा कि कोरोना एडवाइजरी की सख्ती से पालना के लिए ऊंचा स्कूल की अध्यापिका इंदिरा जैन को पाबंद किया गया था। इसके बावजूद गार्डन में आयोजित समारोह की उपखंड अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान मौके पर अध्यापिका इंद्रा जैन अनुपस्थित मिली। इस कारण ड्यूटी में लापरवाही मानते हुए उपखंड अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में उचित उत्तर नहीं देने पर सुसंगत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

नलों में आ रहा गंदा पानी

बागोर @ पत्रिका. कस्बे में लौहारों के मोहल्ले में नौ दिन से नलों में गंदा पानीआ रहा है । इसके बावजूद विभाग सुध नहीं ले रहा है। रघु लौहार ने बताया कि आसपास में कही लीकेज होने से लौहार मोहल्ले के घरों में स्थित नलों में नालियों का गंदा पानी आने लगा है। इससे पीने के पानी की किल्लत हो गई है। जलदायकर्मी को इसकी सूचना दी व ऑन लाइन पोर्टल पर भी शिकायत की। नौ दिन बीतने के बाजवूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मोहल्लवासियों को नौ दिनों से दूसरी जगहों से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। एक तरफ कर्फ्यू दूसरी तरफ पानी की किल्लत। इस महामारी में दूसरी जगहों से पानी लाना खतरे को आमंत्रण देना हो रहा है।

नियम तोड़ने वालों पर किया जुर्माना

सख्ती के बावजूद नहीं मान रहे लोग, बेवजह घूम रहे हैं

गंगापुर में कार्यवाही करते उपखण्ड अधिकारी व अन्य।

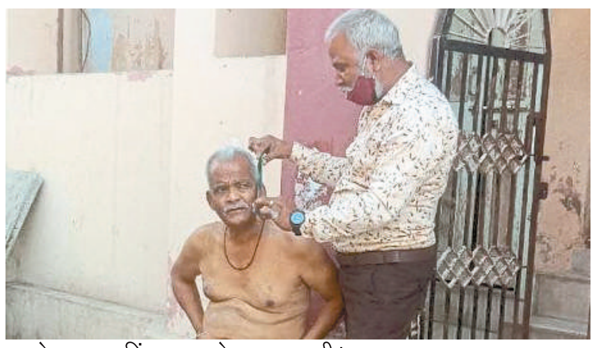

घर के बाहर कटिंग करता सेलून व्यवसायी।

कोटड़ी में एक निजी क्लिनिक के बाहर लगी भीड़।

50 से अधिक वाहन जब्त

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

बिजौलियां. पुलिस ने बुधवार को जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बेवजह घूमने वाले करीब 50 से अधिक दोपहिया वाहनों को जब्त किया और चालान भी काटे। थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिना वजह गांव में घूमने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और सख्त हिदायत भी दी गई है। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश सीमा गुड्डा, आरोली, नाला का माताजी, बिस्वा मिल पर पुलिस चौकी स्थापित की गई है और आने जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। सुबह 11 बजे बाद बाजार पूर्णतया बंद हो जाता है तथा सन्नाटा सा छा जाता है। प्रशासन के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर कोरोना केस का सर्वे कर रहे हैं और दवाइयां भी उपलब्ध करा रहे हैं।द्ध तहसीलदार शैतान सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वे के दौरान जो गंभीर केस है उन्हें रेफर भी करवाया जा रहा है और भामाशाह की तरफ से 40 ऑक्सीमीटर भी दान दिए हैं। उन्हें ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी भिजवाया जा रहा है जिससे रोगी की ऑक्सीजन लेवल की जांच हो सके।

शाहपुरा. कोरोना से 24 घंटे में शाहपुरा के 4 लोगों की मौत के बाद बुधवार को प्रशासन और सख्त दिखा। मुख्य बाजार से मिलने वाले सारे मार्गों पर लोहे के पाईप लगाते हुए वाहनों की बाजार में आवाजाही रोकी। इस कारण बाजार में भीड़ कम दिखी। बाजारों में जहां सन्नाटा पसरा था वही गलियां आबाद दिखी। कई वार्डो में गलियों में व्यवसायी तहसीलदार इन्द्रजीत सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कुलदीप जैन, राजेश शर्मा, पवन बसेर आदि टीम के साथ गलियों में घूमते हुए कई दुकानों को बंद करवाया। कर्फ्यू में घरों में बेच रहे सामान व्यवसायियों को पाबंद किया। इधर पंचायत समिति विकास अधिकारी अमित जैन ने आमली बंगला व ढीकोला आदि ग्राम पंचायतों का दौरा किया और कई दुकानें सीज की तथा चालान बनाए। पुलिस ने भी बीना कारण बाजारों में बाईकों पर घूमने वालों के चालान बनाए। पलिका द्वारा कोविड मृतकों को एंबुलेंस व चार पीपीई किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पारोली. निजी साधनों से अब सुबह 11 बजे बाद घूमने वाले पर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। कोटड़ी पुलिस उपाधीक्षक किशोर बुटोलिया ने बताया कि वृत सर्कल के पारोली मे 20, कोटड़ी 25 और बडलियास थाना क्षेत्र से 16 मोटर साइकिलें सहित कुल 61 मोटरसाइकिल जप्त की गई। कोटड़ी में 17 चालान सोशल डिस्टेंस उल्लंघन तथा पारोली में 10 जनों के चालान बना जुर्माना वसूला है।

पुलिस की सख्ती के बावजूद कई लोग अभी भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आमादा हो रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पारोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक किशोर बुटोलिया ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में पारोली निवासी हाजी उस्मान गनी मोहम्मद उमर, जाकिर, इरफान, इदरीश, अब्दुल जब्बार, अब्दुल मजीद, इलियास तथा लुकमान मोहम्मद को गिरफ्तार किया है।

जहाजपुर. कोरोना की भयावह स्थिति से बचाने के लिए सरकार और चिकित्सक, पुलिस जवान, प्रशासन और अन्य कई संस्थाएं रात दिन जुटी है। लेकिन इनके सफल परिणाम तभी संभव है। जब आप लोगों का साथ बराबर मिले। इस मौके पर जहाजपुर नगरपालिका की ओर से कस्बे में बुधवार को मास्क वितरण करने के साथ ही गली मोहल्लों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा व विधायक गोपीचंद मीणा ने घर-घर जाकर लोगों मास्क वितरण किए और कोरोना की दूसरी लहर की भयावह स्थिति से अवगत कराया।गाइडलाइन की पालना न करने पर दुकानें सील

आसींद. उपखंड क्षेत्र में लोगों द्वारा गाइडलाइन पालना के आदेश निर्देश के बावजूद भी पालना न करने वाले लोगों के खिलाफ उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा सख्त हुए। आसींद मुख्यालय पर निरंतर चाक-चौबंद होते हुए दौरा कर सख्त हिदायत दे रही है। गाइडलाइन की पालना के लिए उपखंड अधिकारी सीएलशर्मा द्वारा कई ग्राम और ग्राम पंचायतों का दौरा कर हालात का जायजा लेते हुए आवश्यक आदेश निर्देश दिए। परासौली में नियमित समय के बावजूद भी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर दुकानें खुली होने पर तीन दुकानें सीज की गई। साथ ही चालान भी काटे गए। बोरियाला, सोपुरा ग्राम सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया गया। साथ ही शादी समारोह सामाजिक कार्यक्रम ऐसे स्थल जहां लोगों की भीड़भाड़ होने की संभावना वाले स्थानों का भी निरीक्षण किया गया।

कोटड़ी. कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप में अनुशासन पखवाड़े लगने से लेकर अब तक कस्बे में लगभग 16 से ज्यादा जिंदगियां कोरोना लील चुका है । लेकिन लोग अभी कोरोना के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। बुधवार को निजी क्लीनिकों व झोलाछापों के बाहर लगी मरीजो की भीड़ क्षेत्र का दर्द बयां करने के लिए काफी है। आगे स्थितियां ओर गंभीर नहीं हो इसके लिए क्षेत्र वासियों को ओर अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। जनता को कुछ हद तक घरो में रखने में पुलिस का योगदान है वह भी केवल कस्बे तक ही सीमित है। गांवो में तो अनुशासन पखवाड़े का कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। थानाधिकारी राजकुमार नायक ने बताया कि बुधवार को अकारण घूम रहे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए लगभग 40 वाहनों के चालान काटे उन्होंने कहा कि जनता से अपील है कि अकारण लोग सड़कों पर नहीं घूमें।

लाडपुरा. कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बिना वजह घूमते हुए लोगों के चालान काटे। चौकी प्रभारी दीवान रामलाल मीणा ने शाम को चेक पोस्ट पर बाहर से आने जाने वाले वाहन चालकों से पूछताछ की तथा सख्ती दिखाई व 15 लोगों के मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले वालों के चालान काटे।

गुलाबपुरा. शहर मे कोविड 19 गाइडलाइन की पालना न करने पर दुकानों एवं बिना मास्क वालों के चालान काटे। लोगों को करोना के प्रति जागरुक कर करोना से बचाव के लिए भी पुलिसकर्मी व स्थानीय प्रशासन समझाइस करते नजर आया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विकासमोहन भाटी, पुलिस उपाधीक्षक लोकेश मीणा, तहसीलदार स्वाति झा, थाना अधिकारी सतीश मीणा, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के गली-मोहल्ले व हम बाजारों में घूम.घूम कर लोगों से घर में रहने की अपील की।

सिंगोली चारभुजा. मोटरो का खेडा पंचायत में कोरोना महामारी के संर मण को रोकने के लिये घर.घर स्वास्थ्य सर्वे किया। कोरोना महामारी के बढते संक्रमण को रोकने के लिये हर परिवार का डोर. टू. डोर सर्वे किया जाकर बुखार,सर्दी, जुखाम के मरिजो की पहचान कर उपचार किया जा रहा है।

पुर. जन अनुशासन कर्फ्यू के तीसरे दिन बुधवार सुबह बाजारों में भीड़ नजर आई। इस दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, कई दुकानों को बंद करवाना पड़ा। पुर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा मय जाप्ता पुर में गश्त पर रहे। बेवजह लोगों के घूमने पर उनके खिलाफ चालान बनाया और वाहन भी जप्त किए।

दुकानों को सीज किया

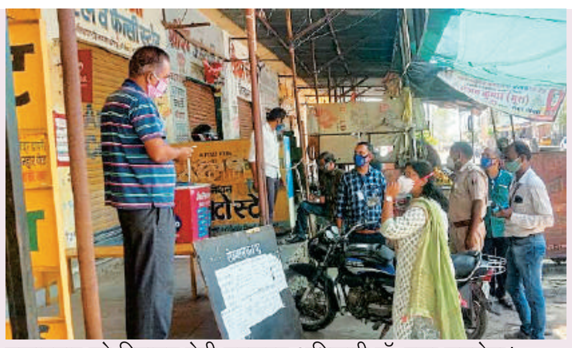

दुकानदार को हिदायत देती उपखण्ड अधिकारी डॉ. पूजा सक्सेना।

मांडल. उपखण्ड अधिकारी डॉ पूजा सक्सेना ने बुधवार को क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने नियमों की अवहेलना करने वाले हरिपुरा चौराहे पर एक क्लिनिक, अजमेर चौराहे पर किराणा, मांडल में फैंसी स्टोर, किराणा, मिठाई की दुकानों को सीज किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने समर्थन मूल्य केंद्र पर भी व्यवस्थापक से खरीद के बारे में भी जानकारी ली। व्यवस्थापक गोपाललाल सर्वा ने बताया कि बाजार में चने के भाव अधिक होने से किसान बेचने नही आ रहे है ।

घरों में जा रहे सेलून वाले

विकराल रूप ले रही कोरोना महामारी के चलते जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सेलून का काम करने वाले लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। कई सेलून व्यवसायी परिचितों के घरों में जाकर हजामत कर रहे हैं।

हमीरगढ़ में आज से कोविड जांच शुरू

हमीरगढ़ क्षेत्र में बढ़ते कोरोनावायरस को देखते हुए कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार से कोविड सैंपल का कार्य शुरू किया जा रहा है। अब हमीरगढ़ क्षेत्र के मरीजों को जिला मुख्यालय पर नहीं जाकर सैंपल हमीरगढ़ में ही लिया जाएगा जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। प्रभारी डॉ महावीर शर्मा ने बताया कि गुरुवार से हमीरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड सैंपल की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गुरुवार सुबह 8 से 10 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का रजिस्ट्रेशन तथा 10 से दोपहर 12 बजे तक सैंपल लिया जाएगा। इसके बाद इन सैंपलों को जिला मुख्यालय भिजवा दिया जाएगा। क्षेत्र में 2 दिन में करीब 8 जनों की मौत हो चुकी है। ग्राम पंचायत द्वारा हमीरगढ़ कस्बे में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है तथा पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है।

Single-window clearance for foreign investors hits a bump

Manpower crunch because of Covid, only 8 states put in place the requisite infra

SHRIMI CHOUDHARY AND SHREYA NANDI
New Delhi, 28 April

ILLUSTRATION: AJAY MOHANTY

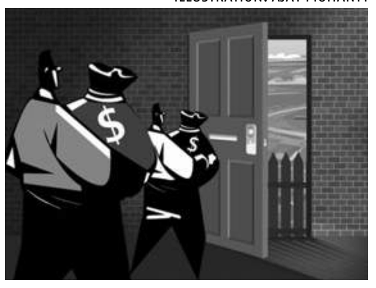

The Centre's ambitious single-window clearance mechanism for foreign investors, which was expected to launch on April 15, has been delayed because states' technical infrastructure is not yet prepared for the new mechanism. Besides, the second wave of Covid-19 and resultant lockdowns have affected manpower availability within the nodal departments.

As a result, it is learnt that the government has worked out a new timeline and has shifted the launch to June.

The new system is being developed to handhold foreign investors keen to invest in India. It aims to help them obtain all requisite regulatory and state clearances to set up manufacturing units here. The portal is also expected to have a repository of the county's land bank, comprising information of all the vacant plots and multiple layers of connectivity, along with satellite views of the terrain.

"There are certain factors that have posed a challenge. First, the magnitude of the land banks is such that identifying them or respective sites for setting up manufacturing units is quite cumbersome. Second, states have to ramp-up their infrastructure to ensure that all available licences/clearance are updated on a single portal for single-window clearance," said a senior government official in know.

It is learnt that a majority of states have not created the technical infrastructure required for the system, which has resulted in Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) coordinating with a few states in the initial phase. The challenges faced by such states are primarily in coordinating with various sub-departments/ministries and collating the necessary information in a single easy-to-understand portal.

In addition, the DPIIT has endeavored to make the portal uniform across India, which has added to the complexity of the matter, said another source aware of the issue.

Sources say that so far, the Centre has managed to get eight states on board, while another seven-eight have not yet given consent for land banks. The DPIIT expected to get at least 15 states on board, including Punjab, Uttar Pradesh, Assam, Gujarat, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu at the time of launch.

"The single-window clearance system intends to provide a one-shot clearance for industrial projects and do away with multiple regulatory approvals/clearances. While the DPIIT had intended to launch the project by April 15, the states that propose to be a part of such clearance will also have to keep their infrastructure ready, so that the entire process is seamless. Further, the lockdown imposed in Delhi as well as the spread of virus has adversely affected the manpower within the concerned ministry. So I think it may take some additional time to be completely ready," said Atul Pandey, partner, Khaitan & Co.

Meanwhile, for domestic investors, the government is working on a national similar window — Maadhyam — which is currently in testing. The portal aims to allow investors to seek approvals required for kick-starting business in India. It is learnt that DPIIT has asked for industry feedback to be submitted by April 27. It will also integrate the existing clearance system of the Centre as well as states.

The portal will allow investors to track their investment proposal, resolve queries, and respond to clarifications raised by government departments on a single platform. While the timeframe for approval will not be revised, respective government departments will know where the investor's proposal is stuck. The portal has more than 650 licences across more than 28 central government departments and 14 states.

"Investors will be able to apply for these central government licences/approvals by filling the Common Registration Form. Further, Maadhyam is integrated with the State Single Window (SWS) of the portal of all the participating States. The investor will be able to apply for the State licenses by filling in the relevant State Registration Form," according to information available on the portal.

Key Challenges

- States to ramp up their infrastructure to ensure that clearance are updated
- Such technical infrastructure has not been created for a majority of states
- Collating the necessary information in a single easy-to-understand portal is cumbersome

About new system

- Single point contact in work for potential investors to attract investments
- Application under different department to be consolidated into one
- So far, eight to nine states on board, awaiting consent from at least 15-20 states
- Scheme will have details of state and district wise industrial and land details

Draft electricity policy bats for pvt investment

SHREYA JAI
New Delhi, 28 April

The draft National Electricity Policy (NEP) — a guiding policy for planning power generation, supply, and investment, under the Electricity Act, 2003, — has laid emphasis on increasing private participation, especially in power distribution in its latest revision. The NEP has also introduced power quality, micro grids, pump hydro storage, real-time power markets in the draft policy statement as key focus areas.

Underlining the most pertinent issue of the sector, the draft has called for major reforms in distribution — "this sector is marred with many inefficiencies like high AT&C losses, inadequate system planning, poor upkeep and maintenance of equipment, etc, which are affecting the financial health of the discoms, and leading to poor consumer satisfaction."

NEP has noted that despite the central government connecting 100 per cent households in the country with the national power supply grid, quality of power and duration remain an issue.

"There is a need to strengthen the distribution system to ensure 24x7 power supply. Also, evolve a unified scheme for development of adequate distribution infrastructure wherein central assistance is linked to reform milestones of the states," said the draft NEP.

The Union Budget announced a revamped reform scheme for discoms, entailing an expenditure of ₹3.05 trillion. The scheme would put the onus on the states to formulate their own action plans and funds would be disbursed accordingly.

The draft has stated that public-private partnership in electricity distribution is one of the effective ways to improve efficiency, enhance consumer satisfaction and reduce financial losses of the discoms. "Franchisee model being one of the PPP models has emerged as a preferred route for introduction of privatisation in the distribution sector. Another variant of the PPP model could be in the form of a sub-licensee power distributor for a particular area."

The suggestions come months after the Centre amended the Electricity Act, 2003, to abolish power "distribution licence" and allowed any company to supply electricity in an area, after necessary regulatory approval. With this, the Centre has ended the monopoly of existing power distribution companies (discoms), which are mostly state-owned entities, and any and every area has been thrown open to be offered to private discoms.

This year's draft NEP, like earlier versions, has underlined the importance of coal-based power and why it is still too early to retire it, despite growth in renewable power. "While India is committed to add more capacity through non-fossil sources of generation, coal-based generation capacity may still be required to be added in the country, as it continues to be the cheapest source of generation, though compliance to stricter environment norms remain a challenge, particularly for older stations," said the draft NEP.

The draft was floated on a public forum by the ministry on Wednesday for stakeholder comments, which must be submitted within two months.

The NEP has introduced several new concepts, starting from the need for micro grids in remote areas to having a real-time power market and need for investment in pump hydro generation.

With the rising capacity of renewable energy generation and lack of balancing sources of energy such as gas and large hydro, the NEP has batted for realising the potential of pump hydro storage. The NEP noted that the country has a potential of 96,524 Mw of pump hydro storage and of that barely 4,785 Mw has been used.

For utilising power generation at the source and reducing wastage, the NEP has suggested that discoms explore the possibility of micro grids, especially in areas prone to natural disasters. The NEP has further said these grids should preferably be powered by renewable sources of energy.

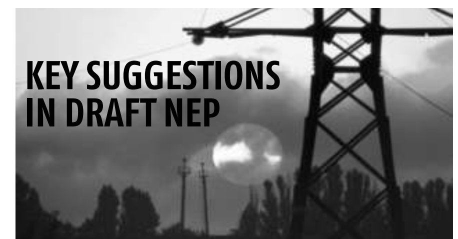

KEY SUGGESTIONS IN DRAFT NEP

- Invite private participation in power distribution
- Ensure quality power supply, especially in rural areas
- Coal-based power to continue to be major contributor in power supply, hence reduce dependence on imported coal
- Enhance use to balancing power such as pump hydro storage, hydrogen storage, etc
- Invest in mini grids, mostly those powered by renewable energy
- Speed up 100% smart metering
- Increase use of indigenous power equipment

Cabinet approves India-UK deal on Customs cooperation

SHREYA NANDI
New Delhi, 27 April

The Union Cabinet on Wednesday approved the signing of a deal between India and the United Kingdom on information sharing and preventing Customs offences.

The agreement is also expected to facilitate trade and ensure clearance of goods traded between the countries, an official statement said.

The deal will be signed on behalf of the governments of the two countries after it is approved by the respective governments. "This Agreement shall enter into force from the first day of the month following signature by duly authorised representatives of both parties," it said.

The agreement will provide a legal framework for sharing of information and intelligence between the Customs authorities of India and the UK and help in the proper application of Customs laws, prevention and investigation of Customs offences and the facilitation of legitimate trade.

The draft text of the proposed agreement has been finalised with the concurrence of the two Customs administrations.

"The Agreement takes care of Indian Customs' concerns and requirements, particularly in the area of exchange of information on the correctness of the Customs value, tariff classification and origin of the goods traded between the two countries," the statement said.

Court stays probe under FIR against Indiabulls Housing

Says charges malafide, casts doubts on bonafide of complainant

BS REPORTER
New Delhi, 28 April

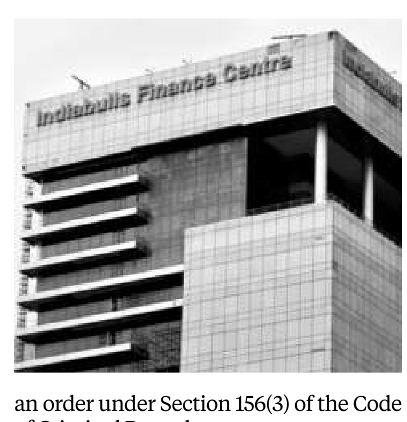

A Division Bench of the Bombay High Court on Tuesday stayed all investigations by the Palghar police regarding a first information report against Indiabulls Housing Finance (IBHL) for allegedly siphoning off funds and for accounting irregularities.

In its order, the court cast serious doubts on the bonafides of the complainant — Ashutosh Kamble, a shareholder of the company.

IBHL had approached the court and the petition was taken up for urgent hearing. The court noted that the Supreme Court has laid down that "interference at the stage of investigation can be justified only in exceptional cases ..."

Noting the malafide intent of the complainant, the court said it is prima facie of the opinion that the complaint "appears to be malafide and deficient".

"It is needless to observe that since we have stayed the investigation, the question of taking further action on the basis of the said FIR would not arise," the court said.

The FIR was filed by police after Palghar's judicial magistrate passed such an order under Section 156(3) of the Code of Criminal Procedure.

The company's counsel told the court that the FIR was nothing but part of a long-running extortion and blackmail saga. Only this time, since blackmailers who had been running this racket from Delhi have been arrested, they chose to rope in a Maharashtra-based accomplice, and this complaint is only a copy-and-paste of earlier patently false and malicious complaints that the blackmailers have been circulating.

The counsel said Kamble had approached the company a few months back and tried to extort money, but IBHL has not succumbed to the threats and extortion attempts of the blackmailers for the last three years, and has chosen to take them on through appropriate legal proceedings. Members of the gang were arrested and have had their bail applications repeatedly rejected by courts, noting their conduct as extortionists and blackmailers in the court orders.

In this case, Kamble, the counsel said, has falsified his residential address to claim favourable jurisdiction of Wada police station in Palghar, where the company has no office or business. He purchased 500 shares of the company just 10 days before lodging the FIR, to create the subterfuge of being an aggrieved shareholder.

In its order, the court acknowledged this and said "prima facie it appears that respondent no. 2 (Kamble) has been set up to initiate criminal proceedings in the matter."

The court was also informed that the Ministry of Corporate Affairs has already examined the books of IBHL and the loans mentioned in the allegations, and has filed a court affidavit saying the loans have either been fully repaid or are standard.

Potential restructuring won't impact business, says ONGC

JYOTI MUKUL
New Delhi, 28 April

The Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) on Wednesday defended its business prospects as also government strategy, stating that the ongoing discussions with stakeholders were helping it raise issues important for the company and any "potential" restructuring would not significantly affect the company.

News agency *PTI* had on April 25 reported the petroleum ministry told ONGC to sell stake in producing oil fields such as to Ratna R-Series to private firms, get foreign partners in the Krishna Godavari basin gas fields, monetise existing infrastructure, and hive off drilling and other services into a separate firm to raise production.

Amar Nath, additional secretary (exploration) in the ministry, on April 1 had written to ONGC Chairman and Managing Director Subhash Kumar giving a seven-point action plan, ONGC Way Forward, that would help the company raise oil and gas production by one-third by 2023-24.

The company did not deny receipt of the letter but said it was also looking into strategic relationships and close alliances with key international players through ONGC Videsh.

The intention is to invite foreign participants to explore Category-II and Category-III basins, which match the size and scale of expectations and portfolio of these large players. "So, it can be stated that the ongoing discussions are neither new nor intended to limit the role or growth of ONGC. Requirement and opportunity for ONGC are to play an even more pronounced role in improving the energy security of the country. ONGC feels confident and comfortable that the ongoing discussions within ONGC and with its stakeholders will help deliver greater value to all stakeholders," said the statement.

ONGC Videsh invokes force majeure in Mozambique project

ONGC Videsh has invoked force majeure in a liquified natural gas project in Mozambique. Considering the evolution of the security situation in the north of the Cabo Delgado province in Mozambique, the Area 1 Operator Total E&P Mozambique Area 1 Limitada informed the withdrawal of all Mozambique LNG project personnel from the Afungi site.

SBI board gives nod for raising up to $2 bn via bonds

State Bank of India (SBI) said its central board in its meeting on Wednesday has approved raising up to ₹2 billion (around ₹14,880 crore) through bonds this fiscal.

The Executive Committee of the Central Board in its meeting on April, 28, 2021 has approved long term [illegible]nd raising in single / multiple tranches up to ₹2 billion, SBI said in a regulatory filing.

The funds are to be raised through a public offer and /or private placement of senior unsecured notes in US dollar or any other convertible currency during FY 2021-22, said SBI.

SBI shares closed at ₹363.30 apiece on BSE, up 2.95 per cent from the previous close. PTI